271

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

ग्रादेश

दिनांक 28 नवम्बर, 1984

ग्रीर वृंकि हरियामा के राज्यवान वित्राद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इतिर, स्रा, प्रौधोगिक विवाद प्रविनियन, 1947 को घारा 10 की उपवारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई गित्रियों का प्रोग करने हुए, हरियागा के राज्यनान इसके द्वारा सरकारी प्रधिभूचना सं० 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 10 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त प्रैविनियन की वारा 7 के प्रवीन गठित श्रम न्यायानय, प्रम्वाना को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिये निर्दिण्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मोमला है :—

क्या श्री ईब्वर बन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. म्रो. वि/यमुना/88-84/42277.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० मनोहर इन्डस्टीज, ग्रीद्योधिक क्षेत्र, सब्जी मण्डी, यमुनानगर के श्रमिक श्री महावीर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामजे में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, भव, भौद्योगिक विवाद भिधितियम, 1947 की घारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी भिधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 10 अप्रैन्न, 1984 द्वारा उक्त भिवित्यम की घारा 7 के अशीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवाद प्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायितिण्य के लिए निद्धि करते हैं, जो कि उक्त प्रश्न को तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्रो महावीर की सेवाग्नों का समापन न्यायोजित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है दिनांक 5 दिसम्बर, 1984

सं. थ्रो. वि./जी. एत / 76-84/43210. - चूँकि हरियाणां के राज्य शत की राये है कि मै. प्रशासक नगर पालिका, रिपाड़ी जिता महेन्द्रगढ़, के श्रीमक श्री कृष्ण सिहतया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विकास है;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतुं निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपवारा (1) के खण्ड (ग) ढारा प्रदान की गई क्र शिक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके ढारा सरकारी अधिसूचना सं 5415—3श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं 11495—जी-श्रम 88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधि-नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम त्यायालय, फरीदाबाद, को विवाद प्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्देष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बंधित मामला है :—

क्या श्री कृष्ण सिंह की सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? वी. पी. सहगल,

संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,